21वीं सदी की नई शिक्षा नीति

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषांक

वर्ष : 2, अंक : 20 | 14 सितंबर, 2020

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के संकल्प को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने 'परीक्षा पे चर्चा' के साथ ही कई नीतियों और योजनाओं को कार्यरूप देना शुरू किया। इसी का परिणाम है कि देश को 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इस नीति में शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के विजन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों की पहचान कर भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने की प्रतिबद्धता जतायी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश की शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता से भरी हो और प्रतियोगी विश्व का सामना करने में सक्षम हो। इसलिए नई शिक्षा नीति ने शिक्षा की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। छात्रों को पाठ्यक्रम और किताबों के बोझ से राहत दी है। यह पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने पर जोर देती है। अब अध्ययन के तौर-तरीके अनुभव आधारित अधिक होंगे।

भारत को एक ज्ञान आधारित समाज में विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को कहीं ज्यादा समावेशी बनाया गया है। नई नीति को 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए काफी लचीली और बहु-विषयक शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसके जरिए हर छात्र की विशेष क्षमता का सदुपयोग किया जा सके।

नई शिक्षा नीति भारतीयता से ओत-प्रोत है। भारतीय भाषाओं, परंपराओं और मूल्यों को जगह देने के साथ ही क्रेडिट ट्रांसफर, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की अनोखी पहल की गई है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, रचनात्मक सोच और इनोवेशन को शामिल कर दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताओं के अनुसार जिन क्रांतिकारी कदमों को उठाने का संकल्प लिया गया है, उनका छात्र, अध्यापक, माता-पिता और सभी राज्य सरकारों ने स्वागत किया है। शिक्षाविदों का कहना है कि इस नीति से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी। यह नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दुनिया में सबसे युवा मानव संसाधन हमारे पास है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस मानव संसाधन को 'नॉलेज पावर' के रूप में पेश किया है और इसके बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। इस नीति में भविष्य के अनुरूप और वैश्विक आवश्यकताओं के मुताबिक युवाओं के नॉलेज और स्किल्स को तराशने पर बल दिया गया है। कुल मिलाकर, नई शिक्षा नीति को जिस स्वरूप में ढाला गया है, वह 21वीं सदी में भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

मोदी सरकार में पहली बार

- स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढांचे में एक बड़ा बदलाव कर स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 का स्वरूप दिया गया है।
- प्ले-स्कूल के शुरुआती साल को भी स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया है।
- शिक्षा का अधिकार जो पहले 6 से 14 साल था, उसका दायरा बढ़ाकर अब 3 से 18 साल किया गया है।
- प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशन सीखे इसके लिए कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए 'परख' नामक 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
- स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है।
- क्रेडिट ट्रांसफर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है।
- देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक यानि भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है।
- वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए 'जेन्डर – समावेशी कोष' की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है।
- जिन जिलों में बड़ी संख्या में वंचित समूह पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' के रूप में नामित किया जाएगा।

जड़ से जग तक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

"नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सिर्फ पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है।"

"नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को, हमारे युवाओं को जिस तरह की शिक्षा चाहिए, जैसी स्किल चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पर फोकस करती है।"

"हमें अपने छात्रों को ग्लोबल सिटिज़न भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटिज़न तो बने, लेकिन साथ-साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से जग तक, मनुज से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक, सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है।"

नई शिक्षा नीति के पांच स्तंभ

1. **एक्सेस**
   (सब तक पहुंच)
2. **इक्विटी**
   (समता)
3. **क्वालिटी**
   (गुणवत्ता)
4. **अफोर्डेबिलिटी**
   (सामर्थ्य)
5. **अकाउंटेबिलिटी**
   (जवाबदेही)

सर्व सुलभ शिक्षा

भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। यह नीति स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। इसमें स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के स्वरूप में बदला गया है। इसमें पहले 5 वर्ष अर्ली स्कूलिंग के होंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

- एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास होगा।
- प्ले स्कूल शहरों और प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब प्ले स्कूल गांवों में भी खुलेंगे। गरीब-अमीर, गांव-शहर, हर जगह और हर व्यक्ति के बच्चे प्ले स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
- टेक्नोलॉजी ने समाज के आखिरी छोर पर खड़े विद्यार्थियों तक पहुंचने का माध्यम दिया है। नई शिक्षा नीति में ई-शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के उपयोग पर जोर दिया गया है। इसके लिए अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा के अधिकार का बढ़ा दायरा

नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अधिकार (RTE) का दायरा बढ़ गया है। यह पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, जो अब बढ़कर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है और उनके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है।

- यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूल में दाखिले से पहले की पढ़ाई (प्री-स्कूलिंग) के लिए सरकारी मदद देने की बात कही है। प्री-स्कूलिंग में प्ले, नर्सरी और केजी स्तर की शिक्षा आती है।
- मूलभूत शिक्षा पर ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा।
- पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे का सीखना ट्रैक किया जाएगा।
- इसके अलावा बच्चों को '21वीं सदी के कौशल' से लैस करने पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए कक्षा 6 से कोडिंग जैसे नए विषयों की शुरुआत की जाएगी।
- सरकार ने इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में 2030 तक नामांकन अनुपात यानि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो (जीईआर) को 100 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में इसे 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है।

दबाव, तनाव और बोझ से मुक्ति

नई शिक्षा नीति में बच्चों की रुचि, प्रतिभा और इच्छाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब बच्चे अपनी रूचि और प्रतिभा के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। स्ट्रीम चयन को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था, वो अब हटा दिया गया है। पहले पारिवारिक इच्छा या दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर कोई स्ट्रीम चुन लेते थे। इससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता था।

- परीक्षा का स्वरूप बदल कर अब छात्रों की 'क्षमताओं का आकलन' किया जाएगा, ना कि उनके यादाश्त का। मार्क्सशीट और नंबरों का दबाव इससे ख़त्म होगा। परीक्षा के मानसिक तनाव से बच्चों को निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है।
- नई शिक्षा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ाई के लिए लंबे-चौड़े सिलेबस और किताबों के बोझ को कम किया गया है।
- नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि शिक्षा केवल डिग्री-डिप्लोमा और नौकरी पाने भर तक सीमित न रहे, बल्कि इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के साथ उनके सोचने-समझने की क्षमता भी बढ़े।

शिक्षा में लचीलापन

मल्टीपल एंट्री-एक्जिट सिस्टम के माध्यम से उच्च शिक्षा को लचीला बनाने की कोशिश की गई है। ग्रेजुएशन में प्रवेश लेकर पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफ़िकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। चार साल बाद की डिग्री शोध के साथ होगी।

- छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए क्रेडिट ट्रांसफर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान किया गया है ताकि छात्रों को अपने पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए बीच में एक कोर्स छोड़ने और बाद में उनका उपयोग करने की स्वतंत्रता हो सके।
- नई शिक्षा नीति मे मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है। अब कोई भी छात्र विज्ञान के साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवीं-बारहवीं बोर्ड और ग्रेजुएशन में चुन सकता है। इसमें कोई एक स्ट्रीम मेजर और दूसरा माइनर होगा।
- अब युवाओं को किसी एक कोर्स में टिके रहने की बाध्यता नहीं है। वे अपने कोर्स से ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स ज्वॉइन कर सकते हैं। अब अपनी पसंद, अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स में दाखिला लेने और छोड़ने की आजादी होगी।

सीखने की ललक

नई शिक्षा नीति पढ़ने के बजाय सीखने पर जोर देती है। इसमें पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने पर ध्यान दिया गया है, ताकि युवा अपनी रुचि के अनुसार कौशल सीख सकेंगे।

- नई शिक्षा नीति 'कैसे सोचें' पर जोर देती है। इसमें बच्चों के लिए सवाल जवाब-आधारित, खोज-आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित और मनोरंजन आधारित सीखने के तरीकों पर बल दिया गया है। इससे कक्षाओं में सीखने और भाग लेने की उनकी ललक बढ़ेगी।

3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला

- नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूले की बात की गई है। पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत के अलावा तमिल, तेलुगू और कन्नड़ जैसी अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- भारतीय संकेत भाषा यानि साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्य सामग्री विकसित की जाएंगी।

शिक्षकों में सुधार

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर चार हिस्सों में बंटा होगा - फाउंडेशन, प्रीपेरेटरी, मिडल और सेकेंड्री। इसी के मुताबिक टीईटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा।

- विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित विषय में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और कॉमन एप्टीट्यूट टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) करेगी।
- शिक्षामित्र, एडहॉक, गेस्ट टीचर जैसे पद धीरे-धीरे समाप्त किए जाएंगे और बेहतर चयन प्रक्रिया का गठन कर स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में नियमित और स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं।
- नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय बीएड डिग्री साल 2030 से न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी। साल 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद शिक्षकों के लिए एक साझा राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की गरिमा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जहां शिक्षक अच्छे पेशेवरों और अच्छे नागरिकों को तैयार कर सकेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा

नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक यानि वोकेशनल शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान बच्चे इंटर्नशिप भी करेंगे ताकि स्कूल से निकलने से पहले कम से कम एक कौशल सीख सके।

- छोटी उम्र से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से बच्चे भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए युवाओं की ग्लोबल जॉब मार्केट में भागीदारी बढ़ेगी।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। सभी व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रणाली का अंग बनाया जाएगा।

"कितने ही प्रोफेशन हैं जिनके लिए डीप स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें महत्व ही नहीं देते। अगर स्टूडेंट्स इन्हें देखेंगे तो एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव होगा, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है बड़े होकर इनमें से कई बच्चे ऐसे ही उद्योगों से जुड़ें, उन्हें आगे बढ़ाएं।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नॉलेज इकोनॉमी

दुनिया में सबसे युवा मानव संसाधन भारत के पास है। नई शिक्षा नीति में 21वीं सदी और वैश्विक आवश्यकताओं के मुताबिक इस अपार संपदा के नॉलेज और स्किल्स को तराशने पर बल दिया गया है, ताकि भारत को एक 'नॉलेज इकोनॉमी' बनाया जा सके।

- भारत के पास पूरी दुनिया में प्रतिभा की जरुरत और प्रौद्योगिकी का समाधान देने की क्षमता है इस जिम्मेदारी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा करती है।
- इस नीति ने ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों के लिए भारत में कैंपस स्थापित करने के रास्ते खोले हैं। इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे।
- 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिट्यूशन बनना होगा। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिट्यूशन होगा।
- शैक्षणिक संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। प्रयोगशालाओं से वंचित छात्रों के लिए वर्चुअल लैब जैसी अवधारणाएं काफी मददगार साबित हो सकती है। गुणवत्ता, योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा।

समान और समावेशी शिक्षा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 'जेंडर – समावेशी कोष' की स्थापना एक नया और क्रांतिकारी कदम है।

- यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके।
- वंचित इलाकों और समूहों के लिए 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' की स्थापना पर जोर दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) की एक समान सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
- एसईडीजी वर्ग की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण किया जाएगा। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को और अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।
- शैक्षिक परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगी।

भारतीयता की महक

नई शिक्षा नीति का विजन ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परंपराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इंडिया की जगह भारत की झलक मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो और भारत दुनिया में एक सुपरपावर के रूप में स्थापित हो।

- सभी पाठ्यक्रमों में जरूरी बदलाव शुरुआती स्तर से ही किए जाएंगे। इसमें भारतीय परंपराओं, मान्यताओं और स्थानीयता की झलक होगी। इसमें संस्कृति, धरोहर, रहन-सहन, भाषा, मनोविज्ञान के प्राचीन और समकालीन ज्ञान को भी शामिल किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम में कहानियां, कला, खेल आदि के उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें भारतीय परंपराओं और स्थानीयता का तत्व शामिल होगा। इसी तरह आदिवासियों की चिकित्सा पद्धति, उनके वन संरक्षण, पारंपरिक खेती के तरीके, प्राकृतिक कृषि आदि के लिए पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।**
- **एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।**
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।**
- **एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।**
- **इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100 प्रतिशत युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।**

6 साल : शैक्षिक समृद्धि

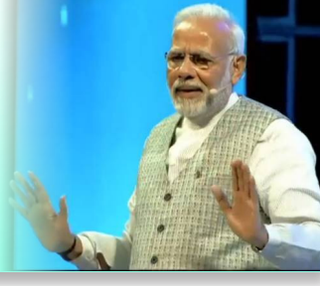

- पीएम मोदी ने विद्यार्थियों से संवाद और परीक्षा के तनाव से मुक्ति का मंत्र देने के लिए 'परीक्षा पे चर्चा' का आयोजन किया।
- बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री नवाचारी लर्निंग कार्यक्रम (ध्रुव) शुरू किया गया।
- मोदी सरकार ने स्कूल जाने वाले एससी के छात्रों के लिए देश भर में अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला लिया।
- मोदी सरकार ने पहले चरण में 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को इंटर कॉलेज तक उच्चीकृत करने की मंजूरी दी।
- बजट 2020 में भारत में पढ़ने की चाहत रखने वाले विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की घोषणा की गई।
- मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की।
- मार्च 2021 तक 150 नए डिग्री/ डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई।
- फरवरी 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड की शुरुआत की।
- जुलाई 2018 में 2022 तक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई।
- संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए तीन संस्कृत शिक्षण संस्थानों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया।
- स्कूलों को Geographic information system से जोड़ दिया गया है। इससे स्कूलों की कमी को पूरा करने में आसानी हुई है।
- मोदी सरकार ने ई-पाठशाला शुरू की, जहां सभी पुस्तकें और अन्य अध्ययन सामाग्री उपलब्ध हैं।
- नवंबर 2015 में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों के मूल्यांकन और विकास के लिए शाला सिद्धि योजना शुरू हुई।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2016 से NIRF रैंकिग सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया।

शैक्षणिक विस्तार

- विदेशी विशेषज्ञों को शिक्षण हेतु भारत बुलाने के लिए 2015 में Global Initiative for Academic Network (GIAN) की शुरुआत की गई।
- घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 2017 में 'स्वयं प्रभा' ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई।
- अप्रैल 2017 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन शुरू किया।
- मोदी सरकार ने देश में 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जाने की मंजूरी दी।
- मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में देश में 462 नए एकलव्य स्कूल खोलने की मंजूरी दी।
- इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2017 में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई।
- स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (मणिपुर) की घोषणा की गई।
- मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 'पढ़ो-बढ़ो' अभियान की शुरुआत की।
- मोदी सरकार ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले के साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति दी।
- पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर लगाम लगाने के लिए स्टूडेंट्स डेटा मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SDMIS) बनाया गया।
- शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDL) की स्थापना की गई।
- IIT संस्थानों में पांच नये अनुसंधान पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दी।
- मोदी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की।
- अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने देशभर में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी।
- मोदी सरकार ने 7 नए आईआईएम और 6 नए आईआईटी खोलने की मंजूरी दी।